भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1699

जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है

अमृतसर में परिवहन अवसंरचना का विकास करना

1699. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर के एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने और घनी आबादी होने के कारण गंभीर सड़क जाम की समस्या है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए मेट्रो प्रणाली, रोप-वे, इलेक्ट्रिक बसें और कैप्सूल लाकर मुद्दों का स्थायी रूप से समाधान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार अमृतसर की परिवहन अवसंरचना को विश्व स्तरीय पर्यावरण-अनुकूल प्रणाली में विकसित करने के लिए विशेष बजट आवंटित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) (i) केंद्र सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा सड़कें राज्य सरकार और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की जिम्मेदारी हैं। अमृतसर के शहरी हिस्से की सड़कें पंजाब राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं।

तथापि, यह ध्यान में रखते हुए कि विरासत, संस्कृति और सामाजिक-धार्मिक महत्व के मामले में अमृतसर देश के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है, भारत सरकार ने यात्रा के अनुभव को बढ़ाने और सड़क मार्ग से अमृतसर की यात्रा करने वाले पर्यटकों की सुविधा में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं।

अमृतसर और उसके आसपास एनएचएआई द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं हैं - अमृतसर संपर्क के लिए स्पर, अमृतसर बाईपास (अटारी-वाघा सीमा पर आगंतुकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए), अमृतसर-रामदास कॉरिडोर (करतारपुर साहिब आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए), अमृतसर-ऊना कॉरिडोर (अमृतसर को आनंदपुर साहिब से जोड़ता है) और ब्यास-बटाला-डेरा बाबा नानक कॉरिडोर (ब्यास को करतारपुर साहिब कॉरिडोर से जोड़ता है) सहित दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे शामिल है।

(ii) 'शहरी नियोजन' राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय सहित शहरी परिवहन अवसंरचना की योजना, आरंभ और विकास के लिए उत्तरदायी हैं।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006, मेट्रो रेल नीति, 2017 और राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) नीति, 2017 तैयार की है, जो शहरी परिवहन प्रणालियों की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शहरी रेल आधारित प्रणाली के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करती है।

वर्तमान में, केन्द्र सरकार को अमृतसर में मेट्रो परियोजना का कोई प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(iii) भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जैसे कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की "पीएम-ई-बस सेवा" योजना और भारी उद्योग मंत्रालय की "पीएम ई-ड्राइव" योजना जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और ईवी विनिर्माण परितंत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य परिवहन निगम सहायता के लिए ऐसे मंत्रालयों को प्रस्ताव भेज सकते हैं।

(iv) सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है। उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय अनुभवों और राष्ट्रीय अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए, एनसीएपी के तहत राष्ट्रीय स्तर का संभावित लक्ष्य 2024 तक कणिकीय पदार्थ सांद्रता में 20%-30% की कमी करना है। 2025-26 तक पीएम10 के स्तर में 40% तक की कमी या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (60 µg/m3) की उपलब्धि हासिल करने के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पंजाब राज्य के अमृतसर शहर सहित 130 मिलियन से अधिक/गैर-प्राप्ति वाले शहरों (लगातार पांच वर्षों तक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) से अधिक वाले शहर) की पहचान की है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इन 130 गैर-प्राप्ति/मिलियन से अधिक शहरों में कार्यान्वयन के लिए शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं और उन्हें कार्यान्वयन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अमृतसर नगर निगम द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भरी गई वार्षिक कार्य योजना की जानकारी के अनुसार, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए अमृतसर शहर में ई-वाहनों के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

•350 ई-रिक्शा/ई-कार्ट खरीदने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

•अमृतसर शहर में 4 ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

*****